



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक पी.बी.आर./निगरानी/रतलाम/भू.रा/2018/1994...

राजस्व मंडल के निदेशानुसार
दो कोर्ट के समक्ष

दिनांक 23/12/17 को
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 04/04/18 नियत।

श्री खरबत सिंह बाबू एड.
द्वारा आज दि. 23/12/18 को
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 04/04/18 नियत।

खरबत सिंह बाबू एड.
राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

- 1- ऊकारसिंह राजपूत पुत्र श्री इन्दरसिंह
- 2- रूगनाथसिंह पुत्र श्री ऊकारसिंह राजपूत

निवासीगण- ग्राम रामगढ, तहसील
पिपलौदा, जिला रतलाम (म.प्र.)

.....आवेदकगण

बनाम

घनकुंवर पुत्र पत्नी राजेन्द्रसिंह राजपूत
निवासीगण- ग्राम रामगढ, तहसील
पिपलौदा, जिला रतलाम (म.प्र.)

.....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता
1959 तहसीलदार महोदय पिपलौदा, जिला रतलाम के क्रमांक
18/अ-12 /17-18 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2017 के विरुद्ध
निगरानी जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

- 1- यहकि अनावेदिका घनकुंवर द्वारा तहसीलदार महोदय पिपलौदा के समक्ष भूमि सर्वे क. 166 रकवा 0.110 हैक्टर के सीमांकन हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अनावेदिका की भूमि से लगी हुई। आवेदक के स्वत्व स्वामित्व की भूमि सर्वे क. 165 रकवा 0.21 हैक्टर स्थित है। जिसे आवेदक द्वारा जर्ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.2002 को कय की थी जिस पर आवेदक भवन बनाकर निवास कर रहा है। आवेदक प्रति निग. का सरहदी है आवेदक को सरहदी भूमि स्वामी होने के बाबजूद भी जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया, और नाही आवेदक को उक्त सीमांकन की कोई व्यक्तिगत सूचना दी गई, एकपक्षीय बालाबाल कार्यवाही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध सीमांकन का आलोच्य आदेश दिनांक 23.12.17 को पारित किया गया।

2- यह कि प्रतिनिगर द्वारा उक्त सीमांकन आदेश दिनांक 23.12.2017 के आधार पर अधीनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(11)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - PBR 10/2018/20/18/19 जिला - रायसेन

स्थान एवं दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

31-7-19

आवेदक की ओर से यह निगरानी... 10/2018/20/18/19
 पिपला हाके प्रकरण क्रमांक 18/31-12/12-18 में पारित
 आदेश दिनांक 23-12-18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-
 राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के
 फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित
 संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु
 कर्मचारी रतलम को भेजा जाता है। उभयपक्ष
 प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14-10-18 को
 कर्मचारी रतलम के समक्ष उपस्थित हों।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य